Affliction of glass grinders with musculoskeletal disorders

1232. SHRI M. A. BABY:

SHRI K. MOHANAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that glass grinders in the country have been found to be suffering from a high incidence of musculoskeletal disorders; and

(b) if so, what preventive measures have been taken to arrest the ailment?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) No such cases of musculoskeletal disorders have been reported. Musculoskeletal disorders are not one of the diseases notifiable under Section 89 of the Factories Act, 1948. However, State Governments have framed rules to prevent risks to the health of the workers employed in glass factories under Section 87 of the Factories Act, 1948.

Import of foreign flag vessels for scrapping purposes

1233. SHRI N. E. BALARAM:

SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have decided to decanalise the import of foreign flag vessels for scrapping purposes;

(b) whether the Metal Scrap Trading Corporation (MSTC) had exclusive rights to import scrap vessels, so far;

(c) if so, whether it is a fact that MSTC has failed to supply scrapships to the ship-breakers; and

(d) if so, what action Government propose to take against the MSTC?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF STEEL IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Due to high prices of scrap ships in the international market and their inadequate availability compared to previous years, MSTC was not able to import scrap ships to the extent required during 1987-88. A package of financial concessions, including reduction in customs duty, in the contribution to Ferrous Scrap Development Fund and in service charges to MSTC has been worked out to make scrap ships purchase more economical at currently prevailing prices. In view of the factors which resulted in scarcity of ships for breaking, no action against MSTC is proposed.

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये नयी कार्य योजना

1234. **श्री रशीद मसूद :**
श्री सुब्रह्मण्यन स्वामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नयी कार्य योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष और कितने क्षत्रफल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ;

(ग) कितनी मात्रा में और किस प्रकार से प्रमाणित बीज एवं खाद किसानों को उपलब्ध कराये जाने का विचार है ; और

(घ) सरकार द्वारा किस-किस स्थान से कितना-कितना प्रमाणित बीज प्राप्त किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान सिंचाई के अन्तर्गत 30 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाये जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत यह प्रस्ताव है कि किसानों को चावल और गेहूं प्रत्येक के एक लाख क्विंटल और मक्का के 40,000 क्विंटल प्रमाणीकृत बीज वितरित किए जाएंगे । यह भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय बीज निगम भारतीय राज्य फार्म निगम और राज्य बीज निगमों के माध्यम से विशेष कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए गेहूं और धान प्रत्येक को एक-एक लाख क्विंटल बीज बफर स्टाक के रूप में रखा जाएगा ।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है, चुनिन्दा जिलों में प्रति जिला 100 अतिरिक्त बिक्री केन्द्र खोलकर प्रति हैक्टेयर 20 किलोग्राम अतिरिक्त पोषक-तत्व इस्तेमाल किए जाने और पहले से ही उर्वरकों का समुचित स्टाक रखे जाने का प्रस्ताव है ।

उर्वरक उद्योग को रियायतें

1235. **श्री रशीद मसूद :**
श्री सुब्रह्मण्यन स्वामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए उर्वरक उद्योग को कतिपय रियायतें दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस राहत का ब्यौरा क्या है और क्या यह राहत किसानों को उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी हां ।

(ख) किसानों को 2350 रुपये प्रति टन यूरिया की सांविधिक अधिकतम उपभोक्ता मूल्य पर 7.5 प्रतिशत की रियायत स्वीकृत की जाएगी । यूरिया की 50 किलो ग्राम की प्रति बोरी पर 8.80 रुपये की रियायत पहली अप्रैल, 1988 से प्रभावी है । उद्योग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यह प्रतिपूरक रियायत पूर्णत: किसानों को मिलनी चाहिए ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Irregularities in Modern Food Industries (I) Ltd.

1236. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether complaints about irregularities, including those against the General Manager, and a demand for a High level Enquiry into the affairs of Modern Food Industries (I) Ltd., Delhi Unit has been received; and

(b) if so, what are the details in this regard and the action taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) and (b) Complaints relating to the affairs of the Delhi unit of Modern Food Industries (I) Ltd. have been received. The allegations made are: purchase of maida during February to October, 1987 from one mill instead of getting tenders/quotations from other mills, irregularities in cash purchases, reduction in production of bread, embezzlement in the despatch section, wrongful deduction from the wages of workmen for the co-operative society, suspension of office bearers and an active member of a union, favouritism in appointment/promotion, etc. The allegations have been looked into and found to be without substance.

Bifurcation of National Film Development Corporation

1237. SHRI RAOOF VALIULLAH:

SHRI SURESH KALMADI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to stall its decision to delink the Directorate of